

मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण

डॉ० मंजू अग्रवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री भार्गव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मथुरा

How to Cite the Article: मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.



<https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i7.2026.117-127>

Keywords	Abstract
	शिक्षा मानव जीवन के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग किया एवं कई आयोगों के गठन से समस्याओं के समाधान भी निकाले। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके अन्तर्गत प्राथमिक बाल्यावस्था में देखरेख, तकनीकी शिक्षा, बटुविपयक, शिक्षा और समग्र मूल्यांकन नीति पर फोकस किया गया। यह नीति शिक्षा को समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विशेष सिफारिश करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शैक्षिक प्रणाली में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। इसका कार्य न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदत्त करना है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने में शिक्षा को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना है। एक शोध पत्र में टम NEP 2020 के प्रमुख उद्देश्यों, उसके सभावित प्रभाव और 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण में इसके योगदान का विश्लेषण करेंगे।



The work is licensed under a Creative Commons Attribution
Non Commercial 4.0 International License

मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

प्रस्तावना

शिक्षा को मानव-जीवन के विकास की जननी माना जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपने जन्म जात व्यवहार, अपनी सभ्यता एवं सस्कृति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करता है। आमतौर पर विद्यालयों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित होने वाली शिक्षा को शिक्षा की संज्ञा दी गयी है।

इसके अन्तर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रणाली व शिक्षण विधियां निहित होती है। इस प्रकार की शिक्षा बालक की एक निश्चित आयु से शुरू होकर एक निश्चित समय तक चलती है। किसी समाज एवं राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा से ही संभव है।

स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति व विकास के सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना गया। भारत में शिक्षा के विकास को दृष्टिगत रखते हुए तथा शैक्षिक समस्याओं का हल खोजने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्तर की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गयी है। सन् 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन कमीशन). 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में लागू की गई। मई 1936 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति 1986 को प्रारूप तैयार करके जारी कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए एक क्रियान्वयन कार्यक्रम (POA) भी तैयार किया। शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में बांटा गया जिनमें कुल 157 बिंदुओं के अंतर्गत शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुआ। भारत सरकार ने एक नीति के क्रियान्वयन तथा उससे प्राप्त अनुभव को देखते हुए सन् 1952 में उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता अनुभव की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कतिपय संशोधन करके कार्यान्वयन के लिए संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 (POA, 1992) कहा गया।

भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। चयन नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित रूप है। उक्त शिक्षा नीति शिक्षा के समस्त स्तरों में गुणवत्तापूर्ण सुधार करके, सम्पूर्ण विकास की ओर अग्रसर करने तथा शिक्षा को और ज्यादा व्यापक और सरल करने हेतु तैयार की गयी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति के अन्दर विद्यालय एवं उच्च शिक्षा में विशिष्ट परिवर्तन एवं परिमार्जन की सिफारिश की गयी। नई शिक्षा नीति अतिरिक्त वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। जो ड्वकीसवी सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति पहुँच, विवटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं जवाबदेही इन पांच महत्वपूर्ण स्तम्भों पर आधारित है।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के युवाओं को वर्तमान एवं भविष्य की अनेक राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में बनाती है। यह नीति विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराती है। ईन शिक्षा नीति के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषय की सीमाओं के बंधन को खत्म करके अपनी इच्छानुसार विषयों को चुनने की स्वतंत्रता दी गयी है, इसके साथ ही मल्टीपल एन्ट्री एवं एग्जिट की नीति ने शिक्षा प्रक्रिया को सरल एवं लचीला बना दिया है।

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की विशेषताएँ

1. नई शिक्षा नीति 2020 की एक मुख्य विशेषता सीक्षणे की ECCE (प्रारम्भिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा) को अपनाना है। NEP 2020 का उद्देश्य बालकों के जीवन के अति महत्वपूर्ण शुरुआती वर्षों पर अधिक ध्यान देकर भारतीय शैक्षिक वातावरण में तेजी से परिवर्तन लाना है। बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा, देने के लिए एनईपी 2020 उनके शैक्षिक जीवन के प्राथमिक वर्षों में सकारात्मक शैक्षिक परिवेश का निर्माण करना, बच्चों के भावनात्मक शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को विकसित करती है। यह नीति बच्चों के प्राथमिक देखभाल, शिक्षा, खेल एवं अनेक गतिविधियों पर आधारित है। उनको सीखने एवं अनुसंधान करना सिखाती है। एनईपी 2020 में ECCE प्रत्येक बच्चे को समावेशी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर अग्रसर करती है।

नई शिक्षा नीति में 3-8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। जिसमें 5+3+3+4 को अपनाया गया है। इसमें 3 साल का आंगनवाडी/प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की मध्य शिक्षा, 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा एवं 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इस नीति में कक्षा 5तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाने का प्रावधान है। इसमें नीति में स्कूल स्तर पर व्यवसायिक विषयों को सीखने के लिए 6-12 के छात्रों को इंटरनशिप के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल या निपुण भारत योजना बनाई गई जिसमें स्थानीय भाषा संसाधनों जैसे-विभिन्न प्राकर की गतिविधियों, खेल कहानी आदि के लिए सुगमता से सीखने की कला निर्धारित की जा सके। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता के द्वारा प्रत्येक बालक कक्षा 3 के अंत में पढ़ना लिखना और गणितीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह रट्टा मार क्रिया को गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया में बदल सकता है।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

आधुनिक शिक्षा नीति में सन् 2025 तक प्रारम्भिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेपरिंग (दीक्षा) ऐप लांच किया गया। जिसमें उक्त विषय पर ऊँचे गुणवत्ता वाले संसाधन सम्मिलित है। यह ऐप शिक्षकों एवं छात्रों के बीच भाषाई विभिन्नता को दूर करने में करता है। यह ऐप बुनियादी साक्षरता को दूर करने में करता है यह ऐप बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सहायता कौशल से अभावग्रस्त बच्चों में गणितीय चिंतन तथा उनके लिए आनन्ददायक व प्रेरणादायक किताबें उपलब्ध कराने में सहायक होगा। ये किताबें सभी स्थानीय एवं भारतीय भाषाओं में होगी।

कुपोषित एवं अस्वस्थ छात्र अच्छे ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 इस परिस्थिति पर भी विचार करती है और उचित कदम उठाती है। इस नीति में कहा गया है। कि स्वस्थ एवं पोषित भाजन एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं तथा स्कूली शिक्षा प्रणाली में समिति की भागीदारी के द्वारा बच्चों के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना चलाई गई।

नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान में दुनिया की परिवर्तित होती परिस्थितियों कठिनाईयों, चुनौतियों एवं आवश्यकताओं से रूबरू होने के लिए स्वस्थ अनुकूली श्रेष्ठ उत्पादक एवं नवमानव तैयार करने के लिए प्रयत्नशील है। यह नीति छात्रों के कौशल निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम एवं एकीकरण को बढ़ावा देती है। बालकों के समुचित विकास के लिए इन कौशलों को अपनाने की जरूरत है। जैसे भाषा दक्षता, मौखिक और लिखित संचार कौशल, कल्याण और खेल, व्यवसायिक प्रदर्शन कौशली, डिजीटल शिक्षा तार्किक रचनात्मक और नीवना, समस्या और समाधान, कोडिंग एवं कम्प्यूटेशनल कौशली, मानवीय एवं असवैधानिक मूल्य, लिंग सवेदनशीलता, पारम्परिक ज्ञान, पर्यावरण जागरूकता आदि। यह नीति मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, जैविक जीवन आदि वैकल्पिक विषयों पर भी चिंतन करती है।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा डिग्री प्रोग्राम की स्वरूप में भी सुधारात्मक परिवर्तन किए गए। इसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं को विविध विषय बनाना स्नातक स्तर की अवधि में लचीलापन, अनुसंधान एवं अनवेषण को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। आज का 3 साल का डिग्री प्रोग्राम कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ तीन एवं चार साल का हो, एकेडमिक बैंक ऑफ़ केडिट को डिजीटल रूप से संग्रहित करता है। स्नातक स्तर के 4 साल के पाठ्यक्रम में 1 साल का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र देगा, 2 साल का पाठ्यक्रम डिप्लोमा देगा. 3 साल का पाठ्यक्रम स्नातक की डिग्री प्रदान करेगा तथा 4 साल का सलेबस अध्ययनरत विषय से संबंधित अनुसंधान और निष्कर्ष को सम्मिलित करेगा। पी०जी० स्तर पर शोध कार्यो को बढ़ावा दिया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों की वित्तीय सहायता हेतु उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) के स्थान पर (एआईसीटीई) एवं यूजीसी लेंगे।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

एमफिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा में आन्तराष्ट्रीय मानक पाने हेतु बहुविषयक शिक्षा तथा अनुसंधान विश्वविद्यालय, स्थापित किए जाएंगे, उच्च शिक्षा में शोध एवं आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन की स्थापना की जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालय को यहाँ पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में सम्मिलित करने की सिफारिश करती है। जो छात्रों के स्कूली स्तर से ही प्रारम्भ हो जाती है। उच्च शिक्षण, संस्थाओं और उद्योगों के मध्य सहयोग स्थापित किए जा रहे हैं। इससे छात्रों को विकास के नए अवसर मिलेंगे। तकनीकी शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए नए अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हो रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एवं डाटा साइंस जैसे नए क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। छात्रों को उनकी योग्यता एवं रुचि के हिसाब से शैक्षिक क्षेत्र चुनने के विकल्प मौजूद हैं। इसमें ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 तकनीकी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को प्रासंगिक, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। तकनीकी शिक्षा के एकीकरण से छात्रों को उद्योगों में रोजगार पा सकेंगे। छात्र जीवन तकनीकी ट्रेड्स और प्रौद्योगिकी जिससे छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा जिस कारण वह नए उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माण एवं विकास पायेंगे जिसके माध्यम सेवाओं का निर्माण एवं विकास कर पायेंगे जिसके माध्यम से उनमें अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने की योग्यता का विकास होगा।

7. नई शिक्षा नीति के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण को धीरे-धीरे स्कूल में एकीकृत करने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कॉलिज व अन्य व्यवसायिक संस्थान भी सम्मिलित हैं। बी कॉम पाठ्यक्रमों को सभी बैचलर पाठ्यक्रमों (3या 4 वर्षों) में एकीकृत किया जाएगा। 2025 तक 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों के पास व्यवसायिक प्रशिक्षण निजी स्तर पर या उद्योगों व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हैं। सामान्य व्यवसायिक प्रशिक्षण के मध्य अंतर हस्तांतरण को कर्ज के सहयोग से आसान बनाया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) में एकीकरण किया गया है। लोक विद्या ओडीएल मोड में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परम्परागत भारतीय विशेषज्ञता को एकीकृत किया है।

नई शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन प्रणाली के तहत कुछ आवश्यक सुधारों की सिफारिश की गयी है। इस नीति में परम्परागत परीक्षा के स्थान पर एक समग्र और अनवरत मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है। जिसके माध्यम से छात्रों की सही योग्यता एवं कौशल को परखना है न केवल रटने की प्रवृत्ति को। इस नीति में वार्षिक परीक्षाओं की जगह पर सेमेस्टर व्यवस्था निर्मित की गई है। छात्रों का प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, समूह



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा प्रणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

गतिविधियों, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के सहयोग नेतृत्व क्षमता एवं टीमवर्क कौशल का मूल्यांकन करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षकों की भूमिका भी कम नहीं है। उन्हें नवीन मूल्यांकन पद्धति का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाने की प्रेरणा दी जा रही है।

यह प्रणाली न केवल विद्यार्थियों के एकेडमिक प्रदर्शन में सुधार करेगी बल्कि उनके समग्र विकास में भी सहयोग करेगी।

एनईपी 2020 और विकसित भारत 2047

विकसित भारत 2047 भारती सरकार का एक व्यापक विजन है जिसका लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है अर्थात् 2047 में प्रत्येक भारतवासी आजादी के 100 वे वर्ष में प्रवीण करते ही एक विकसित भारत में उपस्थित होगा। इस विजन में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण सन्तुलन एवं सुशासन सहित विकास के अनेक पहलुओं को शामिल किया गया है। विकसित भारत का लक्ष्य प्रत्येक भारतवासी के जीवन स्तर में सुधारात्मक परिवर्तन, लाकर सभी को एक समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना है।

भारत को एक विकसित देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति बनाने के उद्देश्य हेतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली अहम भूमिका आदा करेगी। अतः इसी लक्ष्य प्राप्ति हेतु देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रूप प्रदान करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को नवीन रूप प्रदान करना है। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एवं अनुसंधान के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना है। इस नीति को एक सुदृढ़ एवं समृद्धिशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ज्ञान अर्थव्यवस्था:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का विजन 2047 तक भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में तैयार करना है। NEP 2020 में ज्ञान अर्थव्यवस्था का विजन समोवेशी, जीवंत और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित है। जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने में सहायता करेगा। मुख्य बिन्दु इस प्रकार है।

नवचार एवं अनुसंधान:

शिक्षा प्रणाली को नवचार, अनुसंधान एवं रोजगारपरक बनाया जाएगा। नेशनल निसर्च फाउंडेशन (NEF) के जरिए अनुसंधान परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

कौशल विकास और रोजगार परकता:

शिक्षा को कौशल एवं व्यापिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा जिससे युवा रोजगार की योग्यता हासिल करे तथा रोजगार प्राप्त कर सकें।

भातीय ज्ञान प्रणाली:

आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपारिक ज्ञान को एकीकृत करके एक उत्कृष्ट ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, जो भारत को विश्व गुरु के रूप पुनः स्थापना कर सके। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँचा।

इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक उच्च शिक्षा में 100 सकल नामांकन अनुपात (GER) जो समावेशी शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे-दीक्षा) के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा

2040 तक समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों को विविधविषयक संस्थानों में परिवर्तित करना, जो तार्किक निर्णय एवं रचात्मक चिंतन को बढ़ाए।

वैश्विक स्थानीय रकीकरण

इसके तहत प्रावधान निर्मित किया गया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शिक्षा एवं ज्ञान का आदान-प्रदान हो सके।

वास्तव में (NEP) 202 का लक्ष्य एक ऐसे ज्ञान पर आधारित समाज का विकास करना है जो ज्ञान, योग्यता तथा रोजगार पर निर्मित हो एवं 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला रखे।

समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 2047 विजन है शिक्षा जो वंचित वर्गों तक पहुँचाना और जेंडर गैप को कम करना ताकि प्रत्येक बालक विकसित भारत का नागरिक बन सके। शिक्षा व्यावस्था का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक बालक को जन्म या पृष्ठभूमि पर आधारित परिस्थितियों उसके सीखने व आगे बढ़ने में बाधक न बना। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय पाना तथा एक न्यायपूर्ण समाज के प्रमुख बिन्दु: निम्न है।

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह: (SEOGS) नीति में प्रावधान किया गया है कि लिंग के आधार पर, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर किसी भी समूह या व्यक्ति के साथ शिक्षा में भेदभाव नहीं होगा सभी को समान शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होगा।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

लिंग समावेशी कोष:

इस नीति के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट कोष का निर्माण किया जाएगा।

विशेष शिक्षा क्षेत्र:

इसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जायेगा जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए इलाके हैं। उन्हें शैक्षिक स्तर पर मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशन:

इस नीति में स्कूलों को बुनियादी ढांचे एवं विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करके दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को उनकी सुविधानुसार विशिष्ट पठन-पाठन तैयार किया जाएगा तथा उनके लिए शिक्षा को सरल बनाया जाएगा।

पहुँच एवं समानता

इसका लक्ष्य 2030 समस्त स्कूलों शिक्षा के सतरो स्तरों पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करना एवं 2035 तक उच्च शिक्षा में इसे 50 प्रतिशत तक ले जाना।

संवेदीकरण

इसके अन्तर्गत शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में विविधता और समानता के प्रति चेतना उत्पन्न करना तथा सहानुभूति पैदा करना जिससे प्रत्येक बालक गरिमा व आत्मासम्मान के साथ सीख सके।

वैश्विक नागरिकता

नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय मूल्यों (भारतीय दर्शन, परम्परा) के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी समावेश किया गया है, जो छात्रों को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करना सिखाता है। विकसित भारत 2047 विजन में वैश्विक नागरिकता का दृष्टिकोण एक ऐसे भारतीय नागरिक को तैयार करना है जो अपनी संस्कृति एवं मूल्यों में गहराई से जुड़ने के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों को समझने एवं उनका समाधान करने में निपुण हो। 2047 तक भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के विजन में वैश्विक नागरिकता के बिन्दु रस प्रकार है

भातीयता के साथ विश्व कल्याण:

NEP 2020 का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र न केवल ज्ञान व कौशल में निपुण हो बल्कि उनमें वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव भी हो। वे एक जिम्मेदार, रचनात्मक तथा नैतिक नागरिक बने, जो मानवाधिकारों, सतत विकास एवं वैश्विक भलाई के कार्य करते हों।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

सतत विकास म लिए शिक्षा:

2047 के विजन में पर्यावरणीय स्वच्छता सर्वोच्च स्थान पर है छात्रों को शिक्षा के द्वारा जलवायु परिवर्तन, निरंतर जीवन शैली एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करके एक जिम्मेदारी नागरिक बनाना है।

इस विजन के अन्तर्गत युवाओं को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना सिखाए। इसके अन्तर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा साइंस एवं तकनीकी कौशल को सम्मिलित किया गया है। जिससे वे हिन्दुस्तान को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सके।

सांस्कृतिक समग्र एवं सहानुभूति:

इस का लक्ष्य विविधता के प्रति सम्मान, सांस्कृतिक समग्र एवं सहानुभूति को बढ़ाना है ताकि भारत के नागरिक न केवल पूर्णरूपेण आत्मनिर्भरता हासिल करे बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक भूमिका का निर्वाहन कर सके।

“एनईपी 2020 के अनुसार 2047 के लिए वैश्विक नागरिक का अर्थ है- "गर्व से भारतीय, लेकिन सोच से वैश्विक”

आत्मनिर्भरता

विजन 2047 (विकसित भारत) के सपने को साकार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में तकनीकी कौशल एवं शोध के द्वारा योगदान दे रही है। इसका प्रमुख लक्ष्य युवाओं को डिग्री आधारित शिक्षा से हटाकर कौशल आधारित शिक्षा देना है।

आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एनईपी 2020 के प्रमुख योगदान कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा एनईपी 2020 के महत्त्व 6 से ही इंटरशिप एवं व्यवसायिक शिक्षा को प्रारम्भ किया गया है ताकि छात्र बचपन से ही आत्मनिर्भर बन सके।

इस नीति के तहत 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो उन्हें सीधा रोजगार प्रदान करेगा तथा आत्मनिर्भर बनाएगा।

नए युग के कौशल छात्रों को एआई, रोबोटिक्स, क्रोडिंग एग्रीटेक एवं हेल्थकेयर जैसे भविष्य में काम आने वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मातृभाषा में शिक्षा

एनईपी 2020 में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा मातृ भाषा / स्थानीय भाषाओं में दिए जाने की सिफारिश की जा रही है। जिससे जटिल अवधारणाओं को समझना सुगम हो तथा गाँव की प्रतिभाएं भी नवाचार में योगदान दे सके।



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

विविध विषयक एवं लचीली शिक्षा

एकेडमिक बैंक ऑफ़ केडिटस छात्रों को अपनी सुविधानुसार बीच में ही पढ़ाई छोड़ने या बदलने का अधिकार दिया गया, ताकि वे अपने कौशल को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकें।

कौशल एवं डिग्री का एकीकरण उच्च शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण को मद्देनजर रखते हुए डिग्री के साथ-साथ योग्यताधारी युवाओं को तैयार किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार निर्मित कर सकें।

डिजिटल साक्षरता तथा एमवाई भारत

इस विजन के अनतर्गत PM Vidya, DIKSHA व SWAYAM जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा को आसान और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है।

एमवाई भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं के समस्या समाधान हेतु कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का विकास किया जा रहा है, जो विजन 2047 का नेतृत्व करेंगे।

निष्कर्ष

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को नीवन रूप प्रदान करना है। पिछली शिक्षा नीतियां जो मुख्यतया पारम्परागत शिक्षण विधियों पर आधारित थी, उनकी खालियों को दूर करके आवश्यकतानुसार संशोधन करके एनईपी 2020 अधिक गतिशील, अंतर्विषय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो कौशल विकास एवं आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित है। यह नीति विभिन्न विषयों में इंटरनेशनल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को सम्मिलित करके औद्योगिक कुशलता को बढ़ावा देती हैं।

एनईपी 2020 एवं विकसित भारत 2047 का विजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यह नीति एक सुविधाप्रदाता है जो भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकी लाभांश) का सही प्रयोग कर सकती है। यदि इसे उचित तरीके से लागू किया गया तो यह भारत को 2047 तक एक उच्च गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं सशक्त समाज में परिवर्तित कर देगी। एनईपी का लक्ष्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर 2047 तक भारत को विश्व गुरु एवं एक विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.



मंजू अग्रवाल (2026). आधुनिक शिक्षा पणाली 2020 और विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा का रूपांतरण. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(7),117-127.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

REFERENCES

राष्ट्रीय शिक्षा नीति <https://him.wikipedia.org>

गुप्ता राममिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन०सी०आर०टी० 2020

NEP:new Indian National Education Policy 2020 in Ministry of Education India Website 2020

Dr. Goverdhan P.A. Holistic and Multidisciplinary Education. The Important Feature of NEP 2020, India 2021.

New Education Policy government of India. Ministry of Human Resource Development 2020

<https://www.mhrd.gov.in/newp.new>(Last Accessed on 2022 August 10)

National Educational Policy 2020 Overview, Reforms, objective" Indianera.com



**The work is licensed under a Creative Commons Attribution
Non Commercial 4.0 International License**